मद्रास राज्य
बनाम
श्रीमती चंपाकम दोराईराजन
और
मद्रास राज्य
बनाम
सी. आर. श्रीनिवासन
[श्री हरिलाल कानिया सी. जे. फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी, एस. आर. दास और विवियन बोस जे.जे.]

भारत का संविधान:- अनुछेद. 13. 16 (4), 29 (2),46--शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश--कार्यकारी आदेश-विशेष समुदायों के लिए सीटों की संख्या तय करना--अमान्यता-- *धर्म के आधार पर भेदभाव* के खिलाफ मौलिक अधिकार--राज्य के निदेशक सिद्धांत नीति--का मूल्य.

इंजीनियरिंग में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में और राज्य के मेडिकल कॉलेज, मद्रास प्रांत ने एक आदेश जारी किया था (जिसे सांप्रदायिक जी.ओ. के रूप में जाना जाता है) जो सीटें देता है चयन समिति द्वारा सख्ती से भरा जाना चाहिए निम्नलिखित आधार पर, यानी, प्रत्येक 14 सीटों में से 6 थीं गैर-ब्राह्मण (हिंदुओं) को, 2 पिछड़े हिंदुओं को, 2 ब्राह्मणों को, 2 हरिजनों को। 1 एंग्लो-इंडियन और भारतीय के लिए ईसाइयों को और 1 मुसलमानों को:

फुल कोर्ट द्वारा आयोजित (कानिया सी.जे., फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी, एस.आर. दास और विवियन बोस जे.जे.).--कि सांप्रदायिक जी.ओ. का गठन किया गया नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन- कला द्वारा भारत के ज़ेन्स। संविधान के 29(2), अर्थात्, कि "किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा- राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएँ राज्य का धन केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर, भाषा या उनमें से कोई भी और इसलिए अनुछेद. 13 के तहत शून्य था.

संविधान के भाग IV में निर्धारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्हें इसके अनुरूप होना होगा और सहायक के रूप में चलाना होगा।

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि।

निर्णय:सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार--केस संख्या 270 और 1951 का 271

अनुच्छेद 15(1) के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कुछ आवेदनों में मद्रास उच्च न्यायालय के 27 जुलाई, 1950 के फैसले और आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत अपील) और संविधान के अनुच्छेद 29 (2) में परमादेश या अन्य उपयुक्त विशेषाधिकार रिट के मुद्दे के लिए प्रार्थना की गई है जो मद्रास राज्य और उसके सभी अधिकारियों और अधीनस्थों को जी.ओ. को लागू करने, पालन करने, बनाए रखने या पालन करने से रोकता है, जिसमें पालन किए जाने वाले नियम निर्धारित किए गए हैं। राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के मामले में चयन समिति द्वारा।

वी.के.टी. चारी, महाधिवक्ता, मद्रास (आर. गणपति अय्यर, उनके साथ) अपीलकर्ता की ओर ।

अलियादी कृष्णास्वामी अय्यर (अल्लादी कुप्पुस्वामी अय्यर, उनके साथ) उत्तरदाताओं के लिए ।

1951, अप्रैल 9. न्यायालय का फैसला दास जे द्वारा सुनाया गया –

यह निर्णय 1951 के केस नंबर 970 (मद्रास राज्य बनाम श्रीमति चंपकम दोराईराजन) और 1951 के केस नंबर 271 (मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य) दोनों को कवर करता है। सी.आर.श्रीनिवासन) जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो अलग-अलग आवेदनों पर 27 जुलाई, 1950 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ अपील हैं, जिसमें राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के लिए याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की गई है।

मद्रास राज्य चार मेडिकल कॉलेजों का रखरखाव करता है और उन चार कॉलेजों में छात्रों के लिए केवल 330 सीटें उपलब्ध हैं। इन 330 सीटों में से 17 सीटें राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षित हैं और 12 सीटें राज्य द्वारा विवेकाधीन आवंटन के लिए आरक्षित हैं और उपलब्ध सीटों की शेष राशि राज्य के जिलों के चार अलग-अलग समूहों के बीच विभाजित की जाती है।

इसी तरह, मद्रास राज्य में चार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या केवल 395 है। इनमें से 21 सीटें राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षित हैं, 12 सीटें विवेकाधीन छात्रों के लिए आरक्षित हैं। राज्य द्वारा आवंटन और उपलब्ध सीटों का संतुलन जिलों के समान चार अलग-अलग समूहों के बीच बांटा जाता है।

संविधान के प्रारंभ होने से पहले कई वर्षों तक, जिलों के चार अलग-अलग समूहों के बीच विभाजित मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों दोनों की सीटें निर्धारित अनुपात के अनुसार भरी जाती थीं जिसे सांप्रदायिक जी.ओ. कहा गया। इस प्रकार, चयन समिति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक 14 सीटों के लिए, उम्मीदवारों का चयन सख्ती से निम्नलिखित आधार पर किया जाता था:--

गैर-ब्राह्मण (हिन्दू)...6

पिछड़े हिन्दू...2

ब्राह्मण...2

हरिजन...2

एंग्लो-इंडियन और भारतीय

ईसाई 1

मुसलमान...1

उपर्युक्त क्षेत्रीय और सुरक्षात्मक प्रावधानों के अधीन, जिलों के समूहों में से एक विशेष समुदाय के आवेदकों में से चयन शैक्षणिक योग्यता और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर कुछ सिद्धांतों पर किया जाता था। मेडिकल कॉलेजों के मामले में, 20 प्रतिशत से कम नहीं। राज्य के छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से महिला उम्मीदवारों द्वारा भरा गया था, यह चयन समिति के लिए खुला था कि वह किसी भी क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को प्रवेश दे सकती थी यदि उस क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध थे और यदि वे उन नियमों में निर्धारित ऐसे प्रवेशों को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में योग्यता वीजा पर चयन के लिए पात्र थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के बाद भी पुराने सांप्रदायिक जी.ओ. में तय अनुपात का पालन किया गया है। वास्तव में, जी.ओ. नंबर 2208, दिनांक 16 जून, 1950, के चयन के लिए नियम निर्धारित करता है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार पुराने सांप्रदायिक जी.ओ. में निर्धारित सांप्रदायिक अनुपात को काफी हद तक दोहराते हैं।

7 जून 1950 को, श्रीमती चंपकम दोराईराजन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 29 (2) के तहत अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया और मद्रास राज्य और उसके सभी अधिकारियों और अधीनस्थों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन, पालन, रखरखाव या पालन करने से रोकने के लिए एक परमादेश रिट या अन्य उपयुक्त विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की। अधिसूचना या आदेश को आम तौर पर सांप्रदायिक जी.ओ. के रूप में संदर्भित किया जाता है और जिसके द्वारा मद्रास मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को इस तरह से विनियमित करने की मांग की गई थी जो कथित तौर पर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और उल्लंघन। अपनी याचिका के समर्थन में दाखिल हलफनामे से ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता

ने वास्तव में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था. वह बताती हैं कि पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह ब्राह्मण समुदाय से हैं। हालाँकि, प्रवेश के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी वास्तविक आवेदन की अनुपस्थिति के आधार पर उसकी याचिका की विचारणीयता पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके विपरीत, हमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष उसका आवेदन सफल होने पर राज्य उसके लिए एक सीट आरक्षित करने पर सहमत हो गया था। अजीबोगरीब परिस्थितियों में हम इस मामले को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन हम खुद को इस धारणा से बचाना चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिसने वास्तव में किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया है और अनुच्छेद 29 (2) के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए अदालत में आ रहा है।

उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई, 1950 को दिए गए अपने फैसले में श्रीमती चंपकम दोरैराजन के इस आवेदन को अनुमति दे दी। मद्रास राज्य अब हमारे सामने अपील लेकर आया है, जिसका क्रमांक 1951 का केस नंबर 270 है।

श्री श्रीनिवासन, जिन्होंने वास्तव में गुइंडी में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, ने मद्रास राज्य और उसके सभी अधिकारियों को सांप्रदायिक जी.ओ. को लागू करने, पालन करने, बनाए रखने या उसका पालन करने से रोकने के लिए परमादेश या किसी अन्य रिट की प्रार्थना करते हुए एक याचिका दायर की। और जिसके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश को इस तरह से विनियमित करने की मांग की गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 29 (2) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। अपनी याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने मार्च, 1950 में आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा ग्रुप 1 में उत्तीर्ण की थी, उक्त परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और पैराग्राफ 1 में निर्धारित अंक प्राप्त किए। उसका हलफनामा. ऐसा प्रतीत होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए शैक्षणिक परीक्षा के निर्धारण में जिन वैकल्पिक विकल्पों पर विचार किया जाता है, उनमें याचिकाकर्ता श्रीनिवासन ने अधिकतम 450 अंकों में से 369 अंक प्राप्त किए। उच्च न्यायालय ने उसी निर्णय द्वारा इस आवेदन को भी अनुमति दे दी है और राज्य ने एक अपील दायर की है जिसकी संख्या 1951 का 271 है। मद्रास राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने माना कि इन दोनों आवेदकों को उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया गया होगा जहां उन्होंने शामिल होने का इरादा रखते थे और यदि चयन केवल योग्यता के आधार पर किया गया होता तो उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता।

अनुच्छेद 29 जो संविधान के भाग III में "सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार" शीर्षक के तहत आता है, इस प्रकार है:

"(1) भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

यह देखा जाएगा कि जहां खंड (1) नागरिकों के एक वर्ग की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करता है, वहीं खंड (2) व्यक्तिगत नागरिक के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। खंड (2) में उल्लिखित प्रकार के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार एक नागरिक के रूप में एक व्यक्तिगत नागरिक का अधिकार है, न कि किसी समुदाय या नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में। केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नागरिक जो ऐसे किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश चाहता है, उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उसे उस आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे इस अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए निश्चित रूप से नहीं सुना जा सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, यदि उसके पास शैक्षणिक योग्यता है लेकिन उसे केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता का तर्क है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों को संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उनका आग्रह है कि अनुच्छेद 46 राज्य पर लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी रूपों से बचाने का आरोप लगाता है। शोषण का. यह बताया गया है कि यद्यपि इस अनुच्छेद को संविधान के भाग IV में जगह मिलती है जो राज्य के नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है और यद्यपि उस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी उसमें निर्धारित सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। देश के शासन के लिए मौलिक और अनुच्छेद 37 राज्य के लिए कानून बनाने में उन सिद्धांतों को लागू करना अनिवार्य बनाता है। तर्क यह है कि अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सांप्रदायिक जी.ओ. को बनाए रखने का हकदार है.

विभिन्न समुदायों के लिए आनुपातिक सीटें तय करना और यदि उस आदेश के कारण, जिसे कानून में वैध माना जाता है और संविधान का उल्लंघन नहीं है, याचिकाकर्ता शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने में असमर्थ हैं, तो मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है। वास्तव में, मद्रास के विद्वान महाधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनुच्छेद 46 के प्रावधान अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों पर हावी हैं। हम उपरोक्त उल्लिखित तर्कों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बना दिया गया है, भाग III में पाए गए प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, जो अन्य प्रावधानों के बावजूद, अनुच्छेद 32 के तहत उचित रिट, आदेश या निर्देशों द्वारा स्पष्ट रूप से

लागू करने योग्य बनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों का अध्याय पवित्र है और भाग III में उपयुक्त लेख में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, किसी भी विधायी या कार्यकारी अधिनियम या आदेश द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और सहायक के रूप में चलाया जाना चाहिए। हमारी राय में, भाग III और IV में दिए गए प्रावधानों को समझने का यही सही तरीका है। हालाँकि, जब तक किसी मौलिक का उल्लंघन न हो। ठीक है, भाग 1II में प्रावधानों द्वारा प्रदत्त सीमा तक, राज्य को भाग IV में निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह राज्य की प्रदत्त विधायी और कार्यकारी शक्तियों और सीमाओं के अधीन है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत.

आगे यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और यह प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर जन्म, निवास या उनमें से किसी के लिए अयोग्य होना, या राज्य के अधीन किसी रोजगार या कार्यालय के संबंध में भेदभाव किया जाना निम्नलिखित शर्तों में एक विशिष्ट खंड भी शामिल है: -

"(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों की नियुक्तियों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा,

जिसका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन नहीं है।

यदि अनुच्छेद 46 पर स्थापित तर्क ठोस होते तो अनुच्छेद 16 का खंड (4) पूरी तरह से अनावश्यक और निरर्थक होता। हालाँकि, यह देखते हुए कि खंड (4) को अनुच्छेद 16 में डाला गया था, अनुच्छेद 29 से ऐसे स्पष्ट प्रावधान को हटाने को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि संविधान का इरादा राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के मामलों में बिल्कुल भी सांप्रदायिक विचार पेश करना नहीं था। नागरिकों के पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता हो सकती है और उन परिस्थितियों में पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी नियुक्तियों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति राज्य को क्यों दी गई है, इसका कारण समझा जा सकता है। हालाँकि, उस विचार को किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं माना गया था और यह अनुच्छेद 16 के खंड (4) के समान अनुच्छेद 29 से एक खंड को हटाने का कारण हो सकता है।

याचिकाकर्ता श्रीनिवासन का मामला लीजिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने कई गैर-ब्राह्मण उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए और फिर भी कम अंक प्राप्त करने वाले गैर-ब्राह्मण उम्मीदवारों को प्रत्येक 14 में से छह सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता श्रीनिवासन को उनमें से किसी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। प्रवेश न दिए जाने का कारण क्या है सिवाय इसके कि वह एक ब्राह्मण है, गैर-ब्राह्मण नहीं। हो सकता है कि उसने एंग्लो-इंडियन और भारतीय ईसाइयों या मुस्लिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हों, लेकिन फिर भी, उसे बिना किसी गलती के अंतिम उल्लेखित समुदायों के लिए आरक्षित सीटों में से कोई भी सीट नहीं मिल सकती, सिवाय इसके कि वह एक

ब्राह्मण है और नहीं उपरोक्त समुदायों के सदस्य. इस तरह प्रवेश से इनकार को केवल उसकी जाति के आधार पर नहीं माना जा सकता।

यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है क्योंकि वे ब्राह्मण हैं

लेकिन कई कारणों से, जैसे, (ए) वे ब्राह्मण हैं, (बी) ब्राह्मणों को 14 में से केवल दो सीटों का आवंटन है और (सी) दो सीटें पहले से ही अधिक मेधावी ब्राह्मणों से भरी हुई हैं उम्मीदवार। जहां तक ब्राह्मणों के लिए आरक्षित इन दो सीटों का सवाल है, यह सच हो सकता है, लेकिन जब हम अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर विचार करते हैं, तो तर्क की इस पंक्ति में कोई ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां तक उन सीटों का सवाल है, याचिकाकर्ताओं को उनमें से किसी में भी प्रवेश से इनकार केवल उनके ब्राह्मण होने और उस समुदाय का सदस्य नहीं होने के अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं किया गया है, जिसके लिए आरक्षण दिया गया है। सांप्रदायिक जी.ओ. में वर्गीकरण धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर होता है। हमारे विचार में, सांप्रदायिक जी.ओ. में किया गया वर्गीकरण संविधान के विरोध में है और अनुच्छेद 29(2) के तहत नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम ऊपर चर्चा किए गए विशिष्ट लेखों पर अनुच्छेद 14 या 15 के प्रभाव पर विचार करना आवश्यक नहीं पाते हैं।

ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय है कि सांप्रदायिक जी.ओ. संविधान के भाग III में अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण अनुच्छेद 13 के तहत शून्य है। इसलिए, परिणाम यह है कि ये अपीलें लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं। .

अपीलें खारिज.

अपीलकर्ता के लिए एजेंट: पी.ए. मेहता.

उत्तरदाताओं के लिए एजेंट: एम.एस.के. शास्त्री.